भारत सरकार रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. 2006/पी आर/10/31

नई दिल्ली, दिनांक 01/6/2007

महाप्रबंधक/महानिदेशक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ प्रबंध निदेशक, सभी भारतीय रेलें, उत्पादन एवं अन्य इकाइयां सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि (डाक सूची के अनुसार).

> विषयः रेल परिसरों/गाड़ियों में स्थिर (स्टिल)/वीडियो फोटोग्राफी और फिल्म शूटिंग के लिए अनुमति प्रदान करने के संबंध में नीति.

एक फीचर फिल्म की शूटिंग की अनुमित देने में चूकों के संबंध में एक मामले को, (जिसके परिणामस्वरूप पार्टी को उपलब्ध कराए गए कुछ यात्री सवारी डिब्बे जल गए थे/ क्षितिग्रस्त हो गये थे, जिसके कारण रेलवे को बहुत अधिक हानि हुई थी) रेलों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट (1979-80) में दर्शाया गया था. लोक लेखा सिमित (पी ए सी) ने इस मामले के संबंध में कार्रवाई की थी, इससे संबंधित सभी ब्यौरों की जांच की थी और विभिन्न चूकों, विशेष रूप से, शूटिंग के शुरू होने से पहले विस्तृत निबंधनों/शतों का निर्धारण न करना, नुकसान की सीमा निर्धारित करने और उसके लिए दावा दायर करने में अत्यधिक देरी आदि पर प्रतिकूल टिप्पणी की थी. इस पृष्ठभूमि में और रेलवे के हितों को सुरक्षित करने और इस प्रकार की चूकों के दुबारा न होने के मद्देनजर, फिल्म शूटिंग के लिए अनुमित प्रदान करने हेतु शतों को बहुत सख्त बनाने के लिए अनुदेश जारी किए गए थे.

- 2. यद्यपि इन अनुदेशों में उल्लिखित शर्ते मूल रूप से विशिष्ट प्रयोग के लिए रेलवे रोलिंग स्टॉक और अन्य परिसंपित्तयों का उपयोग करते हुए फीचर फिल्मों की शूटिंग के आशय से थी, व्यक्तिगत अथवा वाणिज्यिक प्रयोग हेतु वीडियो फोटोग्राफी, वृत्तचित्र फिल्मों की शूटिंग के लिए सभी अनुरोधों और समाचार फीचर हेतु पेशेवर पत्रकारों से अनुरोधों आदि को भी, (मामला दर मामला आधार पर कितपय छूटों सिहत) अभी तक इन अनुदेशों के अनुसार निपटाया जाता था. यद्यपि स्थिर (स्टिल) फोटोग्राफी के लिए अनुमित प्रदान करने हेतु अनुदेश मौजूद थे, वीडियो फोटोग्राफी के लिए कोई अलग से अनुदेश मौजूद नहीं थे. सभी प्रकार के मामलों में सभी अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने में रेलवे और शूटिंग पार्टियों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर बहुत से अन्य अनुदेश जारी किए गए थे.
- 3. फोटोग्राफिक प्रोद्योगिकी में क्रांति के साथ ही, वीडियो कैमरे का प्रयोग विभिन्न तरीकों (मोबाइल फोनों सिहत) में जनता तक पहुंच गया है और इसकी उपलब्धता और प्रयोग व्यवसायियों तक ही सीमित

नहीं है. इसिलए एक ओर वीडियो फोटोग्राफी, समाचार/फीचरों आदि के लिए शॉट लेना, किसी वृत्तचित्र फील्म की शूटिंग (ये सभी, विशिष्ट प्रयोग के लिए किसी रेलवे रोलिंग स्टॉक/परिसम्पत्तियों की आवश्यकता के बिना) और दूसरी ओर किसी फीचर फिल्म की शूटिंग (रेलवे रोलिंग स्टॉक/परिसम्पतियों की आवश्यकता सिहत या इसके बिना) के बीच एक औचित्यपूर्ण अंतर करना उपयुक्त समझा गया था. इसिलए इस प्रकार के सभी अनुरोधों पर एक समान कार्रवाई करने के स्थान पर आधारभूत वास्तिवकताओं पर विचार करते हुए अनुदेशों को आगे और अधिक युक्तियुक्त बनाने की आवश्यकता थी.

- 4. इसी प्रकार फिल्म शूटिंग के लिए अनुमित प्रदान करने और भारतीय नागरिकों द्वारा बनाई जाने वाली फिल्मों के संबंध में फिल्म शूटिंग के लिए लागू कितपय शतों में छूट देने हेतु अनुरोधों पर विचार करने के लिए भी रेलों/इकाइयों के पास शक्तियां पहले ही हैं. विदेशी नागरिकों द्वारा बनाई जाने वाली फिल्मों के संबंध में भी, रेल मंत्रालय केवल/प्रारंभिक कार्रवाई शुरू करता है और आगे की कार्रवाई हेतु रेलों/इकाइयों को 'सैद्धांतिक रूप में' अनुमोदन भेजता है. तब सभी औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं और संबंधित रेलों/इकाइयों द्वारा वास्तिवक अनुमित दी जाती है. इसे और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए, िक रेलें/इकाइयां शॉट के क्रमों के विवरणें को और इस प्रयोजन हेतु की जाने वाली अपेक्षित व्यवस्थाओं को आकित करने के लिए बेहतर स्थिति में है, यह तर्कयुक्त और उपयुक्त समझा जाता है कि विदेशी नागरिकों द्वारा की जाने वाली फिल्म शूटिंग के लिए लागू शर्तों में छूट के लिए अनुरोधों पर भी संबंधित रेलों/इकाइयों द्वारा विचार किया जाए.
- 5. पूर्ववर्ती पैराग्राफों में उल्लिखित स्थिति को देखते हुए और मामलों के निपटारे में संदर्भ को आसान और कुशल बनाने को सुनिश्चित करने के मद्देनजर, विषय (जहां भी आवश्यकता हो, आशोधनों और युक्तिकरण सिहत) पर लागू संबद्ध अनुदेशों को इस पत्र के अनुबंध में एक सुव्यवस्थित तरीके से समेकित किया गया है. पिछले सभी अनुदेशों को अधिक्रमित माना जाएगा.

6. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमित से जारी किया जा रहा है.

कृपया पावती दें.

भनीष तिवारी)

संयुक्त निदेशक सूचना एवं प्रचार रेलवे बोर्ड

सं. 2006/पी आर/10/31

प्रतिलिपि प्रेषित-

मुख्य जन संपर्क अधिकारी, सभी भारतीय रेलें/इकाइयां आदि (i)

वित्त आयुक्त एवं मुख्य लेखाधिकारी, सभी भारतीय रेलें/इकाइयों आदि (ii) DAID (2017)

(iii) मुख्य सुरक्षा आयुक्त, सभी भारतीय रेलें/इकाइयां

(मनीष तिवारी)

संयुक्त निदेशक सूचना एवं प्रचार रेलवे बोर्ड

सं. 2006/पी आर/10/31

नई दिल्ली, दिनांक 01/6/2007

प्रतिलिपि भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें) 224, रेल भवन, नई दिल्ली Somme aler. (46 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

भारत सरकार रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

No.2006/PR/10/31

New Delhi, Dated: 01/6/2007

The GMs/DGs/CAOs/MDs, All Indian Railways, Production & other Units, Public Sector Undertakings, etc. (As per Mailing List)

Sub: Grant of permission for still/video photography and film shooting in railway premises/trains – Policy regarding

A case relating to lapses in allowing shooting of a feature film (which resulted in burning/damage of some passenger coaches provided to the party causing a huge loss to the Railways), figured in the Report of the Comptroller & Auditor General of India on Railways (1979-80). The Public Accounts Committee (PAC) took up this case, went into all its details and commented adversely on various lapses, particularly, non-settlement of detailed terms/conditions prior to commencement of the shooting, the excessive delay in determining the extent of damage and preferring claim therefor, etc. In this background and with a view to protecting the interests of the Railways and avoiding recurrence of such lapses, instructions were issued making the conditions for grant of permission for film shooting very stringent.

- Although the conditions mentioned in these instructions were basically meant for shooting of feature films utilizing railway rolling stocks and other assets for exclusive usage, till now, all the requests for video photography for personal or commercial use, shooting documentary films and also the requests from professional journalists for news feature, etc used to be dealt with in terms of these instructions (with certain relaxations on case to case basis). Though instructions existed for granting permission for still photography, no separate instructions existed for video photography. Keeping in view the difficulties faced by the Railways and the shooting parties in completing all the required formalities in all types of cases, a number of other instructions were issued from time to time.
- 3. With the revolution in photographic technology, use of video camera has reached the masses in various forms (*including mobile phones*) and its availability and use is no longer confined to the professionals. It was, therefore, thought appropriate to make a reasonable distinction between video photography, taking shots for news/ features, etc, shooting a documentary film (all these *without requiring any railway rolling stock/assets for exclusive usage*) on the one hand and shooting of a feature film (*with or without requiring railway rolling stocks/assets*) on the other. As such, the **instructions needed further rationalization** considering the ground realities instead of dealing with all such requests at par.
- 4. Similarly, Railways/Units already have powers to grant permission for film shooting and also the powers to consider requests for waiver of certain conditions applicable for film shooting in respect of films produced by **Indian nationals**. Even in respect of the films produced by the **foreign nationals**, the Ministry of Railways does

only the initial processing and conveys an 'in-principle' approval to the Railways/Units for further processing. All the formalities are then completed and actual permission granted by the Railways/Units concerned. Keeping this in view and also the fact that the Railways/Units are in a better position to assess the details of the sequences to be shot and the arrangements required to made for the purpose. It is, therefore, considered logical and appropriate that the requests for waiver of conditions applicable for film shooting to be undertaken by the **foreign nationals** also, are considered by the respective Railways/Units.

5. Keeping in view the position mentioned in the foregoing paragraphs and with a view to ensuring ease of reference and efficiency in disposal of cases, the relevant instructions in force on the subject (with modifications and rationalization, wherever necessary) have been consolidated in a systematic manner in the ANNEXURE to this letter. All earlier instructions stand superseded.

| 6. | This | issues | with | the | concurrence | of the | Finance | | Minist | ry of |
|--------|------|--------|------|-----|-------------|--------|---------|---|--------|-------|
| Railwa | ys. | | | | | | |) | , > | |

Please acknowledge receipt.

DA/as above.

Joint Director Information & Publicity
Railway Board

Kaliway Board

New Delhi, Dated: 01/6/2007

No.2006/PR/10/31

Copy for information to:

(i) Chief Public Relations Officers, All Indian Railways/Units.

(ii) FA & CAOs, All Indian Railways/Units.

(iii) Chief Security Commissioners, All Indian Railways/Units...

(Manish Tiwari)

Joint Director Information & Publicity

Railway Board

No.2006/PR/10/31

New Delhi, Dated: 0/6/2007

Copy (with 46 spares) forwarded for information to the Dy. Comptroller & Auditor General of India (Railways), 224, Rail Bhavan, New Delhi.

For Financial Commissioner/Railways.

Copy to:

(i) CRB, FC, MT, ME, MS, MM, ML

(ii) DG/RPF, SECRETARY

(iii) EDF(X) II, JS, DF(X)I, Dir/RPF, Dir/NRM, DPR, DS (G),

(iv) F(X)I, F(X)II, B(C) & Security (Spl) Branches, Railway Board

(ANNEXURE TO BOARD'S LETTER NO. 2006/PR/10/31 DATED 01/6/07)

POLICY GUIDELINES ON STILL/ VIDEO PHOTOGRAPHY & FILM SHOOTING IN RAILWAY PREMISES/ TRAINS

SECTION - A: GENERAL:

1. PRIOR CLEARANCE FROM OTHER MINISTRIES

- Foreign film producers, seeking permission for shooting a **feature film** to be shown/telecast outside India, are required to approach the **Ministry of Information & Broadcasting** for obtaining their **clearance** for shooting in India (at the specified locations). This is also applicable to the Indian producers undertaking the job for a foreign agency or for being shown outside India.
- Foreign film producers, seeking permission for shooting a **documentary film** to be shown/telecast outside India, are required to approach the External Publicity Division of the **Ministry of External Affairs (MEA)** for obtaining **clearance** for shooting in India (at the specified locations). This is also applicable to the Indian producers undertaking the job for a foreign agency or for being shown outside India.
- Professional foreign journalists (not based in India and not having accreditation from the Government of India), are also required to obtain MEA clearance before seeking permission for still/video photography (for news/features to be published/telecast outside India). However, foreign journalists who are based in India and have accreditation from the Government of India do not require such clearance.
- 1.4 Foreign nationals, visiting India as tourists, etc, also do not require such clearance for undertaking still/video photography for personal and non-commercial use.

2. SECURITY CLEARANCE OF LOCATIONS

- 2.1 The locations for still/video photography or film shooting indicated by the applicants (and cleared by the MEA or Ministry of Information & Broadcasting as the case may be and wherever necessary) are generally considered for grant of permission subject to the security clearance in accordance with the guidelines issued by the Ministry of Home Affairs (MHA) from time to time and circulated to the Railways/Units by the Security Directorate of the Ministry of Railways...
- In respect of the requests of foreign nationals, security clearance shall be granted by the Security Directorate of the Ministry of Railways and in respect of the requests from Indian nationals such clearance shall be granted by the Security Departments of the respective Railways/Units.

3. WHOM TO SUBMIT APPLICATIONS

- The requests of the **foreign nationals** (along with the clearance wherever necessary), seeking permission for still/video photography or film shooting in Railway premises/trains, are required to be submitted (either directly by the applicants themselves or through their authorized representatives in India) to the Director Information & Publicity, Public Relations Directorate, Ministry of Railways.
- 3.2 The requests of the **Indian nationals** seeking permission for still/video photography or film shooting in Railway premises/trains are required to be submitted to the Chief Public Relations Officers of the respective Railways/Units depending upon the locations for which permission is sought.
- In both the above cases, the persons/parties seeking such permission should clearly specify the **locations** to be covered, the **likely date(s)** of coverage and the **purpose** for undertaking still/video photography or film shooting.

SECTION - B: STILL/VIDEO PHOTOGRAPHY:

1. GRANT OF PERMISSION

- Permission for still/video photography to **Indian nationals** shall be granted by the Chief Public Relations Officers of the respective Railways/Units.
- 1.2 Permission for still/video photography to the **foreign nationals** shall be granted by the Public Relations Directorate, Railway Board. However, if still/video photography is to be undertaken for commercial purposes, approval (*in principle*) will be conveyed to the concerned Railways/Units advising them to grant permission after completing necessary formalities and charging the prescribed licence fee.
- The **permission letter**, indicating the conditions mentioned in para-1.5 to 1.7 and 2.7 (*wherever applicable*), shall be issued by the Public Relations Directorate Railway Board or the CPROs of the Railways/Units (*as the case may be*) directly to the individual applicants (*or their representatives*) endorsing a copy thereof to the Security Department also.
- In respect of foreign nationals, the **Intelligence Bureau (IB)** shall also be kept informed by endorsing a copy of the permission letter to the Deputy Director/IB, Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi.
- The permission letter issued under para-1.3 is to be treated as authority enabling the applicants to take still/video photographs in railway premises/trains till the validity period indicated therein. The rules/procedure (if any) regulating entry into a particular railway premises, train, etc will have to be followed meticulously. It is clarified that the permission letter, allowing still/video photography, is neither a travel authority nor does it ipso-facto authorize the holder to enter any railway premises/train.

- The holder of the permission letter is required to give **prior information** to the Station Manager/In-charge of the concerned stations/premises before undertaking still/video photography. He has to **observe safety and security regulations** in vogue on the Railways and **ensure that** still/video photography is confined to railway premises/trains only; it does not affect normal working of the Railways; it does not cause inconvenience to other rail users; and it does not cover places prohibited for still/video photography by the Railways
- 1.7 The holder of the permission letter should disclose his/her identity and show the permission letter to the railway officials on demand. In addition, the foreign nationals should have valid Passport/Visa while visiting various locations and they shall be under an obligation to show the same on demand by the local railway authorities.

2. LICENCE FEE

- 2.1 Railways/Units may fix the licence fee for **still photography** for commercial purpose in consultation with their Associate Finance.
- 2.2 Licence fee for **video photography** shall be the same as that applicable for film shooting (indicated under **Section-C**).
- 2.3 While granting permission for **still photography** for **commercial purposes**, Railways/Units may levy the licence fee fixed by them for the purpose.
- 2.4 However, if the video photography is to be undertaken for **professional or commercial purposes**, permission is to be granted following the guidelines pertaining to **film shooting** (mentioned under **Section-C**).
- However, no licence fee need be levied for still photography to be undertaken by the tourists, rail enthusiasts, etc for personal and non-commercial use and professional journalists (Indian or foreign) for news features on Railways.
- Similarly, no licence fee need be levied for video photography (without requiring any railway rolling stocks or special facilities) to be undertaken by the tourists, rail enthusiasts, etc (without using a professional video camera, tripods, lights, etc) exclusively for personal and non-commercial use and professional journalists (Indian or foreign) for news features on Railways.
- In the above two cases (para-2.5 and 2.6), a written undertaking should be taken from the parties to the effect that any commercial use of the shots taken shall be unlawful and that they will fully indemnify the Railways in the event of any such use and also for any other loss/damage caused to the Railways. A mention to this effect may be made in the permission letter also.

SECTION -C: FILM SHOOTING

1. GRANT OF PERMISSION

- Permission for film shooting in respect of the **Indian nationals** shall be processed and granted by the Chief Public Relations Officers of the respective Railways/Units.
- Permission for film shooting in respect of the **foreign nationals** shall initially be processed by the Public Relations Directorate, Railway Board. After examining such requests and obtaining approval (*in principle*) of the Competent Authority, Railways/Units concerned shall be advised to process further for granting permission.
- The foreign party concerned shall also be advised to submit an application along with a copy of the clearance of the MEA or the Ministry of Information & Broadcasting (as the case may be) and other relevant information/documents, including the script of the film and shooting schedule of sequences to the respective Zonal Railways/Units (within whose jurisdiction shooting is to be undertaken) for scrutiny and further processing.
- 1.4 After completion of the necessary formalities, **Zonal Railways/Units concerned** shall grant actual permission in respect of the foreign parties also.
- 1.5 In view of para-1.1 & 1.4 above and also the fact that the Railways/Units are in a better position to assess the details of the sequences to be shot and also the actual arrangements required to made for the purpose, it has been decided that henceforth the requests of the parties (both, the Indian as well as the foreign) for waiver of conditions applicable for film shooting, shall be considered by the respective Railways/Units while processing the case for granting permission for shooting.

2. CONDITIONS APPLICABLE TO FILM SHOOTING

The conditions (mentioned hereunder) are to be followed while granting permission for film shooting.

2.1 Scrutiny of script of the feature films/documentary films/features: Zonal Railways/Units should obtain the detailed script pertaining to the sequences involving railway premises/property and the detailed programme of shooting. The script should be examined and checked from the point of view of safe/normal working of railways and safety of railway property. It should be ensured that there is no adverse publicity and the Railways are not put in a poor light. The party should not be allowed to make any changes in respect of the names of the locations, railway stations, trains, etc. without prior specific permission of the competent authority, i.e. Railway Board. Mere fact that script has been approved, which requires change of name, should not be taken as approval. If on the basis of the detailed script it is seen that there are sequences wherein the railway rolling stocks are likely to get damaged, permission for shooting such sequences should be withheld.

- 2.2 Security deposit in the form of Cash, Bank Draft or Bank Guarantee for any possible damage to Railway property during the film shooting (refer para-3).
- 2.3 Execution of **Comprehensive Insurance** against all possible risks/damage to movable/immovable Railway assets proposed to be used during the film shooting (*refer para-4*).
- 2.4 **Payment of licence-fee** for film shooting as fixed by the Ministry of Railways from time to time (*refer para-5*).
- 2.5 Payment of hire **charges for the railway rolling stocks** (if required) as per the Indian Railway Coaching Tariff fixed from time to time.
- 2.6 Execution of **Indemnity Bond & Agreement** indemnifying the Railways in case of any loss/damage to men and material in the course of shooting (*refer para-6*).
- Observance of safety and security regulations during the shooting. While allowing shooting in the normal run of a train, it may be ensured that shooting by traveling on footboards/roof tops is not allowed. It has to be ensured further that no inconvenience is caused to other passengers. Similarly, shooting should not be allowed on tracks while there is any movement of a train. During the daytime, shooting at crowded railway stations should be avoided to ensure that normal functioning of the railways is not affected adversely and there is no inconvenience to the rail users.
- A liaison officer from Publicity Department should invariably be attached with the shooting team to ensure that there is no large scale departure from the original and accepted script in respect of railway sequences utilsing railway properties (buildings, rolling stocks, tracks, signals, etc.) and Railway personnel. The liaison officer is also responsible to ensure that the shooting team adheres to safety and security instructions and there is nothing detrimental to the image of India or Indian Railways. In case of feature films a liaison officer each from the Commercial and Security Departments should also be attached (in addition to that from the Publicity Department).

3. SECURITY DEPOSIT

- 3.1 A Security Deposit in the form of *cash/bank draft/bank guarantee* is to be taken in advance from the parties desirous of shooting films.
- 3.2 In cases of shooting directly undertaken by the crew of the Films Division, Doordarshan, Film Institutes at Pune & Kolkata and other such government owned Film/TV Training Institutes (without requiring any rolling stock for their exclusive use) no security deposit is to be taken.
- 3.3 The amount of Security Deposit shall **not be uniform** but shall be decided by the General Managers in consultation with the FA & CAOs in each case depending upon the script and sequences to be shot as well as involvement of the rolling stocks.

- 3.4 This amount would be in addition to any other amount of security deposited by the party as per rules laid down in the Coaching tariff.
- 3.5 The **refund of the Security Deposit** shall be made only after completion of the shooting after ensuring that the assets and rolling stocks have been restored in tact without any damage and no damage has occurred to any other Railway property.
- 3.6 It would be the responsibility of the Liaison Officer to report immediately to the authorities, the details of any damage caused to Railway property.

4. COMPREHENSIVE INSURANCE:

- The shooting parties are required to take Comprehensive Insurance against all possible risks/damage of railway assets (movable and immovable including rolling stocks) proposed to be used, as also for death or injury to any person(s) on the Railway property including Railway staff at the time of the shooting of the film with provision for full compensation as decided.
- 4.2 In cases of shooting directly undertaken by the crew of the Films Division, Doordarshan, Film Institutes at Pune & Kolkata and other such government owned Film/TV training Institutes (without requiring any rolling stock for their exclusive use) this formality is not required.
- The insurance amount should be calculated on the basis of **current replacement** value of assets/rolling stocks involved in the shooting.
- 4.4 The parties should deposit the premium of insurance to the Railway Administration who will get the railway assets/rolling stocks/persons insured in its name.
- 4.5 The risk covered should provide for the Insurance Company to pay the insured sums without demur.
- 4.6 In the context of insurance taken out to cover all people on Railway property during the shooting of the film which may result in death or injury to any of them including Railway staff, the compensation amounts/insured amount must be arranged to be paid to the concerned persons or their legal heirs without demur.
- 4.7 A representative of the shooting party is to be associated in case damage caused is required to be assessed. Such assessment should be completed in the shortest possible time.

5. LICENCE FEE

- For undertaking film shooting, a licence fee (as fixed by the Ministry of Railways from time to time) is to be paid in **advance** by the parties.
- 5.2 In cases of shooting directly undertaken by the crew of the Films Division, Doordarshan, Film Institutes at Pune & Kolkata and other such government

- owned Film/TV training Institutes (without requiring any rolling stock for their exclusive use) no licence fee is to be realised.
- There could be cases of cancellation of shooting after payment of the licence fee. If intimation for cancellation is received before making arrangements for shooting, **full refund** of the licence fee should be made. However, **no refund** is to be made if the intimation is received after the arrangements are made.
- The licence fee for film shooting in railway premise/trains (as effective from 01/06/2007) is indicated below:

| S.No. | Classes of cities within whose geographical or civic limits, the railway stations or other railway installations/premises are located. | Licence fee per shooting day (or part thereof) per station/train (or any other railway rolling stock) | | | |
|-------|--|---|--|--|--|
| | (Based on the Classification for the purpose of Compensatory City Allowance Notified by the Government from time to time) | | | | |
| 1 | 'A-1' and 'A' | Rs. 1,00,000/- (Rs one lakh) | | | |
| 2 | 'B-1' and 'B-2' | Rs. 50,000/- (Rs fifty thousand) | | | |
| 3 | Other cities/places | Rs. 25,000/- (Rs twenty five thousand) | | | |
| 4 | Moving/stabled trains (or any other railway rolling stock) | Rs.30,000/- (Rs thirty thousand) | | | |

6. INDEMNITY BOND & AGREEMENT:

- An Indemnity Bond must be executed and submitted by the Producers of the film in favour of the Railways to indemnify the Railways completely against any loss or injury that might occur during the course of shooting to any part of the railway property and personnel.
- This Bond should also make it obligatory for the party to reimburse all claims, demands, suits, losses, damage, costs, etc. to the Railways in case any loss/damage is caused to railway property and death or injury is caused to all or any people thereon including staff on duty during the course of shooting.
- Obtailed terms and conditions for use of railway premises, rolling stocks, staff and other people must be settled in all cases in advance by the Zonal Railways/Units in consultation with the FA & CAOs. There should be no scope for any ambiguity left while drafting such terms and conditions. If necessary, the advice of the legal department may also be taken so that the interest of the Railways is fully protected.

- 6.4 Besides the security deposit and comprehensive insurance, the detailed agreements should invariably provide for an arbitration clause (refer para-7).
- 6.5 In cases of shooting directly undertaken by the crew of the Films Division, Doordarshan, Film Institutes at Pune & Kolkata and other such government owned Film/TV training Institutes (without requiring any rolling stock for their exclusive use), there is no need to execute Indemnity Bond/Agreement. However, a written undertaking should be obtained from the concerned authority at the appropriate level to the effect that any loss/damage to the Railway property/assets will be fully reimbursed by them.

7. ARBITRATION

- 7.1 There should be an arbitration clause in the agreement providing for appointment of an arbitrator only from among the **serving Railway Officers**.
- 7.2 It should also be provided that when cases are referred to an arbitrator, it must be obligatory for the arbitrator to make **a speaking award**.
- 7.3 The arbitrator should record in detail the **specific reasons** for admission or non-admission of the Railways' claims item-wise so that the Railway could examine the reasons and if the grounds set forth by the arbitrator are untenable, the award could be challenged in a court of law.
- 7.4 The arbitrator should list out all the damaged items (item by item) that need replacement or rectification and assess the charges arrived at as well as the reasons for the quantum of amount fixed. Such settlement would naturally cover complete haulage and other commercial charges, which need to be debited for the use of the Railway property/rolling stocks at the location.

8. POWERS TO RELAX CERTAIN CONDITIONS IN SPECIFIED CASES

- 8.1 In respect of shooting of a **feature film**, the conditions applicable for film shooting are **not to be relaxed** (irrespective of the fact whether railway rolling stocks are required or not) as these conditions were laid down following the recommendations of the Public Accounts Committee..
- However, if shooting is proposed to be undertaken by the parties without requiring any rolling stocks or special facilities from the railways for their exclusive use, the General Managers (with the concurrence of the FA&CAOs) may relax certain conditions on specific requests to this effect from the parties in cases specified below:
 - (i) For shooting of a **documentary film** (not involving participation of film stars/personalities), the request for waiver of **Security Deposit** and execution of **Comprehensive Insurance** may be considered provided that the sequences to be shot are not likely to cause any loss/damage to the railway property..
 - (ii) For shooting of documentary films or features by the crew of the television channels (including professional foreign journalists not based in India and not having accreditation from the Government of India) exclusively on any aspect relating to Indian Railways and for shooting assigned to a party by Railway

Board, Zonal Railways/Units and Railway PSUs for their own productions, waiver of Security Deposit, execution of Comprehensive Insurance and payment of licence fee may be considered provided that the sequences to be shot are not likely to cause any loss/damage to the railway property.

- (iii) Shooting by the cameramen/ photographers, correspondents (Indian or foreign but accredited by the Government of India or the State Governments) for news coverage or features on Railways to be telecast on the respective television channels, waiver of Security Deposit, Comprehensive Insurance, license fee, submission/execution of indemnity bond/agreement may be considered provided that the sequences to be shot are not likely to cause any loss/damage to the railway property. A suitable written undertaking at the appropriate level should, however, invariably be taken to the effect that any loss/damage to railway property/assets will be fully reimbursed by them. General Managers (with the concurrence of the FA&CAOs) may authorize the CPROs to grant permission in such cases.
- (iv) In respect of video photography for professional or commercial purposes, the procedure mentioned at (i) above may be followed.
- (v) For video photography by tourists/rail enthusiasts (without using a professional video camera) exclusively for personal and non-commercial use, the procedure mentioned at (iii) above may be followed. The individuals may further undertake in writing that any commercial use of the shots taken shall be unlawful and they will fully indemnify the Railways for this.
